बुधवार , 28 अक्टूबर 2026, ठाणे, मुंबई

दैनिक सिटी न्यूज मुंबई

सच का जोश

वर्ष - 15 • अंक - 63

CITY NEWS MUMBAI

ज्ञानेश कुमार को हटाए बिना चैन से नहीं बैठेंगे

कांग्रेस का दावा- बैठक के लिए नहीं मिली अनुमति, दिल्ली पुलिस ने कहा- कोई बदलाव नहीं

इंडी गठबंधन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग कार्यक्रम की योजना बनाई थी, जिस पर कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस द्वारा अनुमति रद करने का आरोप लगाया है। इंडी गठबंधन की पार्टियों ने रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली अपनी रैली से पहले, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक 'सार्वजनिक महाभियोग' कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई थी। जिसको लेकर कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच नया सियासी टकराव शुरू हो गया है। दरअसल, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली मेगा रैली से पहले होटल 'अशोका' में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की मंजूरी पुलिस के दबाव में रद की गई और रामलीला मैदान में भी तैयारी करने से रोका गया। 30 अक्टूबर के कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलने का आरोप केसी वेणुगोपाल के अनुसार, यह कार्यक्रम 30 अक्टूबर को होना था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए पार्टी को



रामलीला मैदान में 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की अनुमति मिली हुई थी। इसके बावजूद 30 अक्टूबर को कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं दी गई? वेणुगोपाल ने कहा कि परसों हमारे लोग यहां कार्यक्रम की तैयारी करने आए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हमें नहीं पता कि इसकी क्या वजह है। उन्होंने आगे आरोप लगाया, 'इसका मतलब यह है कि यह दिल्ली पुलिस का निर्णय नहीं है। यह पीएम मोदी और अमित शाह का निर्णय है और वे अपने कठपुतली ज्ञानेश कुमार की रक्षा कर रहे हैं।' दिल्ली पुलिस ने हमें तैयारी करने से रोक दिया- वेणुगोपाल वेणुगोपाल ने दिल्ली पुलिस पर रामलीला मैदान में कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रही पार्टी को रोकने का भी आरोप लगाया। उन्होंने एक्स पर किए एक पोस्ट में लिखा, 'आप कितनी अनुमतियों से इनकार करेंगे, अमित शाह? आप कितने लोगों को रोकेंगे? इंडिया ब्लॉक की 21 पार्टियों ने 1 नवंबर की मेगा रैली और मार्च के लिए ज्ञानेश कुमार पर सार्वजनिक महाभियोग की योजना बनाई थी। पहले होटल अशोका में, जहां अनुमति से इनकार कर दिया गया था, और फिर रामलीला मैदान में, जहां पहले से ही सभी आवश्यक अनुमतियां होने के बावजूद, दिल्ली पुलिस ने हमें कार्यक्रम के लिए तैयारी करने से रोक दिया था। पहले उन्होंने चुनावी व्यवस्था को बर्बाद किया,...शेष 7 पर

दिवाली से पहले फडणवीस कैबिनेट ने लिये 12 बड़े फैसले, किसानों से लेकर ST महामंडल तक, जानें किसे क्या मिला?

दिवाली से पहले महाराष्ट्र की फडणवीस कैबिनेट ने किसानों, दिव्यांगों और ST कर्मचारियों समेत 12 बड़े फैसले लिए हैं। जानें किसे क्या मिला और इस बैठक की मुख्य बातें। महाराष्ट्र कैबिनेट ने किसानों और ST महामंडल के लिए बड़े फैसले लिए बैठक में कृषि और सिंचाई समेत कुल बारह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए राज्य सरकार के इन ऐतिहासिक फैसलों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की हालिया बैठक में राज्य के सर्वांगीण विकास, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और विभिन्न सामाजिक वर्गों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कई ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगाई गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में कृषि, सिंचाई, ढांचागत विकास, उद्योग, विमानन और



प्रशासनिक सुधारों से जुड़े 12 प्रमुख फैसले लिए गए। किसानों को दिवाली से पहले 5,000 का अग्रिम तोहफा राज्य के 304 सूखाग्रस्त तालुकाओं के लगभग 1.5 करोड़ किसानों के लिए दिवाली का त्योहार बड़ी राहत लेकर आया है। मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि जिन किसानों की फसलों का 33 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, उन्हें 5,000 की अग्रिम सहायता राशि दी जाएगी। यह धनराशि बिना किसी बिचौलिए के सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना का विस्तार ग्रामीण इलाकों में खेत-सड़कों के निर्माण को बढ़ावा देने वाली 'मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना' को 'विकसित भारत - जी राम जी योजना' तथा अन्य योजनाओं के समन्वय से जारी रखा जाएगा। इसे अब जिला स्तरीय योजना के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे जिला नियोजन समिति (DPC) के कोष से कार्य कराए जा सकेंगे। इसके साथ ही, मैदानी स्तर की व्यावहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य स्तरीय समिति को विशेष अधिकार सौंपे गए हैं। दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए 1% बजट आरक्षित राज्य में दिव्यांगजनों के पुनर्वास, कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक संवेदनशील फैसला लिया गया है। अब जिला वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) के अंतर्गत कुल बजट का 1% फंड विशेष रूप से दिव्यांगजनों की योजनाओं और कल्याणकारी कार्यों पर खर्च करने को मंजूरी दे दी गई है। जल संसाधन विभाग का पुनर्गठन कृषि उत्पादन बढ़ाने और जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए ...शेष 7 पर

महाराष्ट्र SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस, 2 करोड़ नाम हटाने पर मांगा जवाब



महाराष्ट्र में SIR प्रक्रिया के तहत करीब 2 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। मसौदा मतदाता सूची से करीब 2.07 करोड़ नाम हटाने को चुनौती; 1.22 करोड़ नामों पर भी सवाल। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र एसआईआर को चुनौती देने वाली सीए अरुण आनंद गिरि द्वारा दायर याचिका पर केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग तथा अन्य को नोटिस जारी किया है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता ...शेष 7 पर

मुंबई, ठाणे और भिवंडी के निवासियों के लिए अलर्ट, BMC ने अगले 7 दिनों तक पानी उबालकर और छानकर पीने की दी सलाह



मुंबई, ठाणे और भिवंडी के निवासियों के लिए BMC ने जारी किया अलर्ट। जल आपूर्ति नेटवर्क की मरम्मत के चलते अगले 7 दिनों तक पीने का पानी उबालकर और छानकर पीने की दी गई है सलाह। बीएमसी ने मुंबई, ठाणे और भिवंडी के लिए जारी किया पानी का अलर्ट। मरम्मत कार्य के चलते अगले सात दिनों तक पानी उबालकर पीने की सलाह। पिसे-पांजरापुर परिसर के येवाई मास्टर बैलेंसिंग रिजरवायर की पूरी हुई है मरम्मत। BMC ने मुंबई शहर के कुछ प्रमुख हिस्सों, ...शेष 7 पर

यह न तो नेपाल है, न बांग्लादेश और न ही श्रीलंका... विपक्ष पर भड़के एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को साजिश बताते हुए कहा कि बिना सबूत के आरोप लगाने वाले देशद्रोही हैं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर लगाया साजिश का आरोप सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति के सामने सबूत पेश करने में विपक्ष नाकाम बिना सबूत के आरोप लगाने वाले लोगों को बताया देश का गद्दार फिहाल पूरे देशे में विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला जा रहा है और वोट चारी के गंभीर आरोप लग रहें है। ऐसे समय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में मीडिया से बात करते



हुए विपक्ष पर करारा हमला बोला है। विपक्ष पर भड़के एकनाथ शिंदे ने सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों को सरकार को बदनाम करने की एक गहरी साजिश करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत पेश करने में विफलता महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब देश की सर्वोच्च अदालत ने विपक्ष से उनके द्वारा दावा किए गए सबूत पेश करने को कहा, तो उनके पास प्रस्तुत करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था। इसके अलावा, राष्ट्रपति द्वारा भी जब सबूतों की मांग की गई, तब भी विपक्ष कोई सबूत देने में पूरी तरह नाकाम रहा। बिना सबूत आरोप लगाने वाले देशद्रोहीः एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री ने बिना किसी सबूत के आरोप लगाने पर विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि ऐसे लोग देश के गद्दार हैं और देश विरोधी काम कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे के अनुसार, विपक्ष का मुख्य एजेंडा देश को खंडित करना और हर तरफ अराजकता फैलाना है। यह नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका नहीं, यह भारत है विपक्ष पर ...शेष 7 पर

रामलीला मैदान में रैली से पहले बीजेपी की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा, केंद्रीय नेतृत्व होंगे शामिल

बीजेपी देशभर में कांग्रेस के खिलाफ पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। इस यात्रा में केंद्रीय नेतृत्व भी शामिल होगा। बीजेपी 28 अक्टूबर को 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा निकालेगी भाजपा अभियान के तहत देशभर में पदयात्रा निकालेगी केंद्रीय नेतृत्व पदयात्रा में शामिल होंगे भारतीय जनता पार्टी बुधवार को अपने 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के तहत देशभर में पदयात्रा आयोजित करेगी। इन कार्यक्रमों में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अपने-अपने क्षेत्रों में शामिल होने की उम्मीद है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली में होने वाली पदयात्रा में हिस्सा लेंगे, जो चांदनी चौक इलाके में आयोजित की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल होंगी राष्ट्रीय राजधानी में होने वाली इस पदयात्रा में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के भी शामिल होने की संभावना है। भाजपा यह यात्रा विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए निकाल रही है।



विपक्ष लगातार चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर बीजेपी को घेर रहा है। दिल्ली में, यह पदयात्रा दोपहर 2 बजे लाल किले से शुरू होकर चांदनी चौक स्थित टाउन हॉल की ओर जाएगी। इस पदयात्रा में 15,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। झूठा नैरेटिव को उजागर करेगी भाजपा का लक्ष्य इन कार्यक्रमों के जरिए विभिन्न राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को एकजुट करना है। वरिष्ठ नेताओं के इन पदयात्राओं में शामिल होने से पार्टी के अभियान को मजबूती मिलेगी और वे जनता तक अपनी बात पहुंचा सकेंगे। इस यात्रा को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' अभियान के माध्यम से भाजपा प्रदेशभर में जनता के बीच जाकर कांग्रेस के झूठ और फेक नैरेटिव को तथ्यों के साथ उजागर करेगी। जानकारी के अनुसार, पदयात्राओं और जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से बीजेपी जनता को जागरूक करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और प्रदेश में सुशासन के प्रति जनविश्वास को और मजबूत करेगी। इंडिया गठबंधन की रैली की तैयारी एक ओर बीजेपी पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली की तैयारी हो रही है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल 1 नवंबर को इस रैली के साथ अपनी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। इस दौरान चुनाव आयोग की कार्यशैली और वोट चोरी के कथित मुद्दों पर घेरा जाएगा।

खरगे की पीएम मोदी पर टिप्पणी से नाराज मायावती? कांग्रेस को दी नसीहत, बोलीं- जहरीली राजनीति देशहित में नहीं

मायावती ने मल्लिकार्जुन खरगे की पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस को नसीहत दी। उन्होंने नेताओं से व्यक्तिगत हमलों और कटु बयानबाजी से बचने की अपील की। मायावती ने पीएम मोदी पर खरगे की टिप्पणी को लेकर बयान दिया उन्होंने व्यक्तिगत हमलों और विषैली बयानबाजी से बचने की अपील की बसपा प्रमुख ने राजनीतिक व्यवस्था पर जनता के भरोसे को लेकर चिंता जताई उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लेकर बड़ा बयान दिया है। बसपा प्रमुख ने पीएम नरेंद्र मोदी पर खरगे द्वारा की गई विवादित टिप्पणी को लेकर कहा कि राजनीति में व्यक्तिगत हमले



और विषैली राजनीति देशहित में नहीं के लिए सही नहीं हैं। बसपा प्रमुख ने बिना नाम लिए कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में आपसी अविश्वास, द्वेष, कटुता और आरोप-प्रत्यारोप का स्तर अब व्यक्तिगत स्तर पर भी काफी बेलगाम हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे देश की गरिमा और मान-मर्यादा पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। बेलगाम हो गया है आरोप-प्रत्यारोप का स्तर मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में आपसी अविश्वास, द्वेष, कटुता और आरोप-प्रत्यारोप का स्तर अब व्यक्तिगत स्तर पर भी काफी बेलगाम हो गया है। यह असंसदीय, अमर्यादित, अपमानजनक, संकीर्ण और जातिवाद से ग्रसित होते हुए हिंसक बयानबाजी तक पहुंच रहा है, जो अति-दुखद और देश की गरिमा व मान-मर्यादा के लिए चिंताजनक है। शीर्ष नेताओं को मर्यादा बनाए रखने की सलाह उन्होंने कहा कि शीर्ष स्तर पर आसीन लोगों के बीच यदि एक-दूसरे के लिए समुचित सम्मान नहीं है, तो कम से कम आपत्तिजनक और विषैली राजनीति को किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। मायावती का इशारा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की ओर था। बसपा प्रमुख मायावती के मुताबिक, बढ़ती संकीर्ण और गरीब-विरोधी स्वार्थी राजनीति के कारण लोगों का भरोसा राजनीतिक व्यवस्था पर कमजोर होना देश और जनहित में नहीं होगा। बसपा प्रमुख ने सरकारी स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार और चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों का भी उल्लेख किया।

चक्रवात अर्णव आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा, 140 KM की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट



चक्रवात अर्णव आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है। 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। जानें दिल्ली, यूपी और बिहार के मौसम का हाल। चक्रवात अर्णव बंगाल की खाड़ी से आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है। तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 115–125 किमी/घंटा और झोंके 140 किमी/घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 20 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान 'अर्णव' तेजी से ताकतवर हो रहा है और आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, तूफान के 28 अक्टूबर की सुबह तट से टकराने की आशंका है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के लिए अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में प्रशासन ने बचाव और राहत की तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के 20 राज्यों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, 12 विपक्षी पार्टियों की संयुक्त याचिका को साथ सुनेगा कोर्ट



राहुल गांधी समेत 12 विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मामला SIR प्रक्रिया, मतदाता सूची की गड़बड़ियों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली से जुड़ा है। राहुल गांधी समेत 12 विपक्षी नेताओं ने संयुक्त याचिका दाखिल की याचिका में SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए विपक्ष ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया की जांच मांगी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत 12 विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से दायर संयुक्त रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस याचिका में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं। मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. एसएस संधू तथा डॉ. विवेक जोशी को अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं। WP(C) नंबर 1351/2026 के तहत दायर यह याचिका मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष संबंधित मामले के रूप में सूचीबद्ध की गई है।

रेलवे के नए नियम आज से लागू, काउंटर से टिकट लेने वालों को भी मिलेगा 10 लाख तक का बीमा; डिजिटल पेमेंट जरूरी



रेलवे काउंटर से टिकट लेने वालों के लिए नया नियम लागू। अब 45 पैसे में यात्रा बीमा मिलेगा, लेकिन प्रीमियम का भुगतान सिर्फ डिजिटल माध्यम से होगा। 27 अक्टूबर से रेलवे काउंटर से टिकट पर भी 45 पैसे में यात्रा बीमा का विकल्प मिलेगा। बीमा प्रीमियम का भुगतान केवल डिजिटल माध्यम से किया जा सकेगा। दुर्घटना की स्थिति में पात्र यात्रियों को 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिल सकता है। रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए 27 अक्टूबर 2026 से नई सुविधा शुरू की गई है। अब काउंटर से रिजर्व टिकट लेते समय यात्री भी 45 पैसे देकर वैकल्पिक यात्रा बीमा ले सकेंगे। हालांकि, इसके लिए नकद भुगतान नहीं किया जा सकेगा और प्रीमियम की रकम डिजिटल माध्यम से ही जमा करनी होगी। इससे पहले यह सुविधा ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे बोर्ड ने इसे काउंटर बुकिंग तक बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में टिकट खरीदते समय जानिए, बीमा कैसे मिलेगा और दुर्घटना होने पर कितना कवरेज मिल सकता है। क्या है रेलवे का नया नियम? अब तक ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को बुकिंग के दौरान वैकल्पिक यात्रा बीमा लेने का विकल्प मिलता था। वहीं, रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 6 अक्टूबर के आदेश के बाद रेलवे बोर्ड ने इस व्यवस्था को काउंटरों तक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी यात्रा बीमा का विकल्प देना है। नई व्यवस्था के तहत यात्री टिकट खरीदते समय बीमा का विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए उन्हें 45 पैसे का प्रीमियम देना होगा। यह राशि डिजिटल माध्यम से ही जमा की जा सकेगी।

बीमा लेने के लिए क्या करना होगा? अगर आप रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से टिकट खरीद रहे हैं और यात्रा बीमा लेना चाहते हैं, तो टिकट बुक करते समय कर्मचारी को इसकी जानकारी दे सकते हैं। बीमा का विकल्प चुनने पर 45 पैसे का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। ध्यान रखें कि यात्रा बीमा लेना अनिवार्य नहीं है। यात्री चाहें तो बिना बीमा के भी अपना रिजर्व टिकट खरीद सकते हैं। लेकिन अगर वे बीमा का लाभ लेना चाहते हैं, तो नकद भुगतान का विकल्प नहीं मिलेगा। रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, काउंटर से खरीदे गए टिकट पर मिलने वाली बीमा पॉलिसी की शर्तें ऑनलाइन टिकट के लिए लागू शर्तों जैसी ही होंगी।

पटना में मतगणना केंद्र पर हंगामा, CCTV नहीं होने पर कांग्रेस-जन सुराज ने उठाए सवाल

बिहार MLC चुनाव में पटना मतगणना केंद्र पर CCTV कैमरे नहीं होने को लेकर कांग्रेस और जन सुराज ने सवाल उठाए। संजय यादव ने धरना दिया, जबकि अनुज सिंह ने अपनी जीत का भरोसा जताया। पटना में CCTV कैमरे नहीं होने पर संजय यादव ने धरना दिया जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह ने भी मतगणना व्यवस्था पर सवाल उठाए अनुज सिंह ने पटना स्नातक सीट पर बड़े अंतर से जीत का भरोसा जताया बिहार विधान परिषद की सीटों पर आज मतगणना की जा रही है। इसी बीच पटना में मतगणना केंद्र पर कांग्रेस नेता संजय यादव ने धरना शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि मतगणना स्थल पर CCTV कैमरे नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि जब तक कैमरे नहीं लगाए जाते, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। जन सुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह ने भी मतगणना केंद्र पर CCTV कैमरे नहीं होने का मुद्दा उठाया है। जन सुराज के एमएलसी चुनाव प्रत्याशी अनुज सिंह ने अपनी जीत का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि मतदाता अपना फैसला सुना चुके हैं और उन्हें उम्मीद है कि जीत उन्हीं की होगी। अनुज सिंह के मुताबिक, जन सुराज पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट बड़े अंतर से



जीतने जा रही है। हालांकि, उन्होंने मतगणना की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। मतगणना स्थल पर CCTV नहीं होने का आरोप जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह का कहना है कि जिन स्थानों पर वोटों की गिनती की जा रही है, वहां CCTV कैमरे नहीं लगाए गए हैं। उन्होंने इस व्यवस्था को लेकर चिंता जताई और अपनी आपत्ति रिटर्निंग ऑफिसर के सामने रखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे केंद्र में कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन जिस जगह मतगणना हो रही है, वहां CCTV की व्यवस्था नहीं है। अनुज सिंह ने इसे धांधली बताते हुए कहा कि जब तक मतगणना स्थल पर कैमरे नहीं लगाए जाते, उनका धरना जारी रहेगा। मतगणना केंद्र की साफ-सफाई पर भी उठाए सवाल जन सुराज प्रत्याशी ने मतगणना केंद्र पर साफ-सफाई की व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण मतगणना के दौरान काउंटिंग एजेंटों के बैठने की जगह बेहद गंदी है और वहां से बदबू आती है। उनके मुताबिक, इस तरह की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पटना डीएम ने CCTV को लेकर क्या कहा? पटना स्नातक सीट की मतगणना के दौरान CCTV कैमरे नहीं होने की शिकायत पर पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव की मतगणना में CCTV कैमरे नहीं लगाए जाते हैं और सभी उम्मीदवारों को इस संबंध में पहले ही जानकारी दी गई थी। डीएम के मुताबिक, प्रशासन भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक काम कर रहा है। इस बीच चुनाव के नतीजों को लेकर मतगणना केंद्र के बाहर प्रत्याशियों के समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है।

रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की हुंकार! तैयारी का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल

दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन की रैली की तैयारी चल रही है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल तैयारी का जायजा लेने मौके पर पहुंचे। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली केसी वेणुगोपाल तैयारी का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस पर बाधा डालने का आरोप लगाया दिल्ली के रामलीला मैदान में निर्वाचन आयोग के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। कांग्रेस 1 नवंबर को इस रैली के साथ अपनी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। इस बीच कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को दिल्ली के नेताओं के साथ कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि रैली की तैयारियों के लिए दिल्ली का पूरा नेतृत्व अभी यहीं मौजूद है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर काम हो रहा है। उन्होंने आगे कहा



कि कार्यक्रम में इंडिया ब्लॉक और देश भर से अन्य प्रतिभागी शामिल होंगे। पुलिस पर कांग्रेस का आरोप कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की 1 नवंबर की रैली से पहले प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों में पुलिस ने बाधा डाली। वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ने पहले अशोका होटल के लॉन में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक अन्य स्थान पर बुनियादी ढांचा तैयार करने से रोक दिया। दवाब के आगे नहीं झुकेंगे कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रस्तावित 30 अक्टूबर का कार्यक्रम कथित चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ 1 नवंबर की रैली और मार्च के लिए एक प्रारंभिक कार्यक्रम के रूप में योजनाबद्ध था। वेणुगोपाल ने केंद्र पर मतदाता सूचियों और कथित अनियमितताओं पर विपक्ष को चिंता जताने से रोकने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि हम उनके दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। हम जानते हैं कि कार्यक्रम कैसे आयोजित करना है और कहा कि पार्टी अपनी अगली कार्रवाई की घोषणा करेगी। 21 राजनीतिक दलों के शामिल होने की उम्मीद वेणुगोपाल ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार असहमति को दबाने और राजनीतिक दलों को उसकी कार्रवाई की आलोचना करने से रोकने का प्रयास कर रही है। 1 नवंबर की रैली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में होने वाले कार्यक्रम में लगभग 21 राजनीतिक दलों के भाग लेने की उम्मीद है।

इंडिया ब्लॉक "वोट चोरी" के खिलाफ लगातार चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है।

गुवाहाटी फायरिंग पर उठ रहे सवाल! कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने हिमंता बिस्वा सरमा पर साधा निशाना



गुवाहाटी में सोमवार की रात फायरिंग की घटना पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सवाल उठाया है। उन्होंने सीएम हिमंता विस्वा सरमा से जिम्मेदारी लेने को कहा। गुवाहाटी में फायरिंग से कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल बोरा सर्विस इलाके में स्थित होटल बिलास इन के पास फायरिंग फायरिंग की घटना पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बयान असम के गुवाहाटी में सोमवार की रात अंधाधुंध फायरिंग की घटना ने राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना पर असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने जताई है।

मंगलवार को गुवाहाटी के उलुबारी इलाके में होटल बिलास इन के पास हुई गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हो गई। उन्होंने अधिकारियों से इस घटना की गहन जांच करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। एक्स पर एक पोस्ट में, गोगोई ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और गुवाहाटी में सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता जताई।

तमिलनाडु की जेल में बड़ी सेंधमारी! पुलिस पर हमला करके 17 कैदी हुआ रफ्फू चक्कर, हो रही ताबड़तोड़ छापेमारी



तमिलनाडु में 17 कैदियों ने पुलिस पर कथित तौर पर हमला करके जेल से फरार हो गया। पुलिसन ने एक को पकड़ने में कामयाब रही है। तमिलनाडु के एक जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक की घटना सामने आई थेनी उप-जेल में बंद 17 कैदी फरार हो गया एक कैदी को पकड़ने में पुलिस कामयाब रही है तमिलनाडु के जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक की घटना हुई है। थेनी उप-जेल में बंद सत्रह कैदी सोमवार देर रात एक पुलिसकर्मी पर कथित तौर पर हमला करने के बाद फरार हो गए। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से एक कैदी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी फरार कैदियों को पकड़ने के लिए 17 विशेष टीमें गठित की गई हैं। दक्षिण जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजयेंद्र बिदारी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान एक फरार कैदी को गिरफ्तार किया गया।

ब्रिक्स फोरम में बिरला का संदेश, चर्चाओं से नहीं ठोस नतीजों से तय होगी सफलता

ब्रिक्स संसदीय फोरम 2026 में ओम बिरला ने जन-केंद्रित विकास, वैश्विक शांति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए संसदों को सशक्त बनाने की जरूरत बताई। ब्रिक्स की सफलता ठोस परिणामों से तय होगीः ओम बिरला। वैश्विक शांति और सहयोग के लिए संसदों की अहम भूमिका। जन-केंद्रित विकास, युवा सशक्तीकरण और पर्यावरण पर जोर। नई दिल्ली में आयोजित 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जन-केंद्रित विकास और वैश्विक शांति को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स की सफलता केवल चर्चाओं से नहीं, बल्कि उनसे निकलने वाले ठोस परिणामों से तय होगी। बिरला ने सदस्य देशों की संसदों से अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने और साझा प्रतिबद्धताओं को प्रभावी नीतियों में बदलने का



आह्वान किया। उन्होंने कहा कि युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद, कूटनीति और आपसी विश्वास जरूरी हैं। साथ ही उन्होंने युवा सशक्तीकरण और सतत विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा? लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से मंजूरी मिलना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब जरूरत इन प्रतिबद्धताओं को ठोस परिणामों में बदलने की है। उन्होंने कहा कि कानून निर्माण, बजट, विचार-विमर्श और निगरानी के माध्यम से संसदें साझा उद्देश्यों को हासिल करने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। वैश्विक शांति के लिए सहयोग जरूरी ओम बिरला ने कहा कि दुनिया इस समय क्षेत्रीय संघर्षों, युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, व्यापारिक तनाव, आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इन समस्याओं का समाधान केवल संवाद, कूटनीति और आपसी सहयोग से संभव है। संसदें विभिन्न देशों के बीच विश्वास मजबूत करने और वैश्विक चुनौतियों का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज मजबूत करने पर जोर उन्होंने कहा कि ब्रिक्स का उद्देश्य ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त बनाना है। इसके लिए साझा आकांक्षाओं को ठोस नीतियों और व्यावहारिक सहयोग में बदलना जरूरी है। इस वर्ष संसदीय फोरम का विषय 'जन-केंद्रित विकास हेतु संसदों को सुदृढ़ बनाना' है।

सम्पादकीय

लोकतंत्र पर हमले का एक असफल प्रयास

हालांकि तख्तापलट का प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भारत विरोधी ताकतें अपने प्रयास बंद कर देंगी। आने वाले समय में आम नागरिकों को भारत विरोधी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है। भारतीय लोकतंत्र को विश्व भर में सम्मान प्राप्त है। ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के बाद, भारतीय लोकतंत्र का अध्याय डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर द्वारा संविधान के निर्माण के साथ शुरू हुआ। डॉ. अंबेडकर ने कई देशों की घटनाओं और लोकतांत्रिक प्रणालियों का अध्ययन करके भारतीय संविधान की रचना की। समय के साथ, लोकतांत्रिक प्रणालियों की लंबी विरासत वाले अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र में भी लोकतंत्र की सीमाएं उजागर हुईं। हालांकि, भारतीय लोकतंत्र आज भी कई देशों के लिए एक आदर्श बना हुआ है। इस लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से भारत एक विकसित देश बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यही कारण है कि भारत विरोधी ताकतें कई वर्षों से विभिन्न माध्यमों से भारतीय लोकतंत्र पर हमले करके इस प्रणाली को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। 2014 के बाद से इन प्रयासों को और गति मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक एक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के अपने दृढ़ संकल्प को अक्सर व्यक्त किया है। विश्व के कई शक्तिशाली देश भारत की विकास की दिशा में चल रही प्रगति को लेकर चिंतित हैं। कई अंतरराष्ट्रीय समूह लोकतांत्रिक प्रणाली में भारतीय नागरिकों के विश्वास को डगमगाने के उद्देश्य से भारत के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए काम कर रहे हैं। इन समूहों को भारत में ही भारत विरोधी ताकतों का समर्थन प्राप्त है। NEET प्रश्नपत्र लीक कांड और मतदाता सूची से नाम हटाने के अभियान के विरोध प्रदर्शनों ने भारत विरोधी ताकतों को बेनकाब कर दिया है। मोदी सरकार ने इन भारत विरोधी ताकतों की योजनाओं को नाकाम कर दिया है। यूरोप के कई देशों में हो रही हिंसा और इसी दौरान भारत में हुए प्रदर्शनों में शामिल कई तत्व अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर सामने आए हैं। भारतीय लोकतंत्र में ऐसे कई हमलों को विफल करने की क्षमता है। तीन महीने पहले NEET परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद, राजधानी में अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसमें छात्रों ने मास्क पहन रखे थे। प्रश्नपत्र लीक की घटना पर आम जनता की प्रतिक्रिया बेहद आक्रोशपूर्ण थी। मोदी सरकार ने इस जनभावना को तुरंत ध्यान में रखते हुए, इस परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से निष्पक्ष बनाने के लिए कड़े फैसले लिए। प्रदर्शनकारी अचानक संसद की ओर बढ़े और कई सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। इस मार्च में शामिल समूहों ने पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमला किया। प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इस तनावपूर्ण स्थिति को बड़ी संयम से संभाला। इस प्रदर्शन के जरिए देश में हिंसा फैलाने की योजना को नाकाम कर दिया गया। पांच-छह साल पहले नई दिल्ली की सीमा पर किसानों का प्रदर्शन, नई दिल्ली में 'CAA' (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के खिलाफ शाहीन बाग का प्रदर्शन, इस बार भी प्रदर्शनकारी पुलिस द्वारा गोलीबारी किए जाने के स्पष्ट इरादे से काम कर रहे थे। शाहीन बाग के प्रदर्शन के बाद दिल्ली में हुए दंगे इस बात का सबूत थे कि देश में अराजकतावादी ताकतें बहुत सक्रिय हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है, भारत में मुसलमानों को मोदी सरकार के खिलाफ सुनियोजित रूप से भड़काया गया, यह अफवाह फैलाकर कि मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। पिछले सात-आठ वर्षों में देश में हुए प्रदर्शनों का तरीका एक जैसा है। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों में भी इसी तरह के प्रदर्शन हुए। इन दोनों देशों में हिंसा के परिणामस्वरूप तख्तापलट हुआ। प्रदर्शनकारी 'NEET' प्रश्न पत्र लीक और मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान के खिलाफ हिंसा का सहारा लेने के इरादे से सक्रिय थे, ताकि पुलिस और सुरक्षा बल इस हिंसा को नियंत्रित करने के लिए गोली चलाएं और इससे देश में हिंसा का तूफान आ जाए। भारतीय संविधान और लोकतंत्र की परीक्षा लेने वाला यह आंदोलन उम्मीद के मुताबिक विफल रहा। देश में सत्ता परिवर्तन की साजिश कामयाब नहीं हो सकी। भारतीय लोकतंत्र पर यह हमला इसलिए नाकाम हुआ क्योंकि भारतीय नागरिकों ने अराजकतावादी ताकतों के उकसावे में आने के बजाय इस आंदोलन से दूर रहने का फैसला किया। छात्रों, अभिभावकों, युवाओं और आम जनता की भावनाएं NEET प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ काफी मजबूत थीं। इसीलिए जुलाई में दिल्ली में हुए आंदोलन को आम जनता की सहानुभूति मिली। मोदी सरकार ने इस परीक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए कई नीतिगत फैसले लिए। नंदन नीलेकानी जैसे विशेषज्ञ को परीक्षा प्रौद्योगिकी प्रणाली में सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रश्नपत्र लीक में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इसके बावजूद, प्रदर्शनकारियों ने संसद पर मार्च करके और पुलिस पर हमला करके अपने छिपे इरादे उजागर कर दिए। यह स्पष्ट था कि जब आम भारतीय नागरिक को आंदोलन के पीछे की अराजकतावादी साजिश का पता चला तो यह आंदोलन विफल हो जाएगा। छात्र प्रदर्शनों के दौरान, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी मोदी सरकार प्रदर्शनकारियों को संतुष्ट नहीं कर पाई। हालांकि मोदी सरकार ने समन्वय के लिए एक कदम पीछे लिया, लेकिन प्रदर्शनकारी दिल्ली छोड़ने को तैयार नहीं थे। उस समय प्रदर्शनों को मिली लोकप्रियता और जनसमर्थन ने प्रदर्शनकारियों को और उग्र बना दिया। इससे मतदाता सूची को बहाना बनाकर सड़कों पर हिंसक प्रदर्शनों की धमकी फिर से दी गई। छात्र प्रदर्शनकारियों को मिली लोकप्रियता और प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी को अपने अस्तित्व का डर सताने लगा। इसी डर से राहुल गांधी ने संसद और सुप्रीम कोर्ट पर मार्च निकालकर अपनी कथित आक्रामक छवि को मजबूत करने का बेताब प्रयास किया।

तकनीक आधारित विकास को गति

फरवरी 2006 में पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कहा था, 'समाज में परिवर्तन लाने का सबसे महत्वपूर्ण आधार मुख्य रूप से विज्ञान से ही आएगा।' लगभग दो दशक बाद कलाम जी के ये शब्द पूरी तरह सही सिद्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तकनीक आधारित विकास को गति देते हुए 'विकसित भारत' की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत की इस प्रगति पर पूरी दुनिया का ध्यान गया है। वैज्ञानिक प्रगति का वास्तविक मूल्य लोगों के जीवन को बेहतर बनाने, समस्याओं का समाधान करने और नए अवसर पैदा करने की उसकी क्षमता में निहित है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षाएं केवल आर्थिक विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं हैं। इनमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, अधिक उत्पादक कृषि, मजबूत उद्योग, युवाओं के लिए अधिक अवसर और प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर में सुधार भी शामिल हैं। इन सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि हम जो ज्ञान विकसित करें, वह सार्थक बदलाव लाने का माध्यम बने। यही उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन (ईएसटीआईसी) 2026 का व्यापक उद्देश्य है। आज से आरंभ हो रहा इसका दूसरा संस्करण ईएसटीआईसी 2025 में शुरू हुए राष्ट्रीय संवाद को ही आगे बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और उनके व्यावहारिक उपयोग के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। यह सम्मेलन विज्ञानियों, नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के अग्रणी लोगों, उद्यमियों और युवा शोधकर्ताओं को एक साझा राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए एक मंच पर लाता है। आज हमारे सामने कुछ ऐसे सवाल हैं-वैज्ञानिक प्रगति किसानों की उत्पादकता बढ़ाने में किस तरह मदद कर सकती है? अनुसंधान के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है? उद्योग उन्नत प्रौद्योगिकियां विकसित कर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं और आयात पर निर्भरता कैसे कम कर सकते हैं? युवाओं के लिए नए अवसर कैसे पैदा किए जा सकते हैं? इनके जवाब कोई एक संस्थान या विषय अपने दम पर नहीं दे सकता। इसके लिए विज्ञानियों को उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करना होगा, शोधकर्ताओं को व्यावहारिक जरूरतों को समझना होगा और नीति-निर्माताओं को ऐसा वातावरण तैयार करना होगा, जिसमें संभावनाओं से भरे विचारों को परखा और विकसित किया जा सके। ईएसटीआईसी इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्नत विनिर्माण, ऊर्जा प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, महासागर विज्ञान एवं समुद्री प्रौद्योगिकी, क्वांटम संचार, सेमीकंडक्टर, कृषि प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, उन्नत स्वास्थ्य सेवा, इमर्सिव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान को समाहित किए हुए है। इनका दायरा प्रयोगशालाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में प्रगति भारत की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत कर सकती है। जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान स्वास्थ्य सेवाओं और विनिर्माण में नई राह खोल सकता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स में होने वाले विकास औद्योगिक प्रक्रियाओं को बदल सकते हैं, जबकि कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य अधिक कुशल एवं टिकाऊ कार्यप्रणालियों को बढ़ावा दे सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती इन संभावनाओं को व्यावहारिक उपयोग में बदलने की है। भारत की वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाएं अंततः उसके युवाओं की प्रतिभा पर निर्भर करेंगी। किसी शोधार्थी के पास कोई उपयोगी विचार है, तो उसे प्रस्तुत करने, अनुभवी विज्ञानियों से सीखने और ऐसे लोगों से जुड़ने का अवसर मिलना चाहिए, जो उस विचार को उपयोगी रूप देने में मदद कर सकें। ईएसटीआईसी इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करता है। 'नेक्स्ट-जेन डिस्कवरी एक्सपो' में देश की अनुसंधान क्षमताओं और उभरते डीप-टेक तंत्र को दिखाया जाएगा, जबकि 'इनोवेशन एक्सचेंज हब' तकनीकों और संभावित सहयोग के अवसरों पर संवाद को बढ़ावा देगा। वैज्ञानिक अनुसंधान और उद्यमिता को तेजी से एक-दूसरे का पूरक बनना होगा। अनुसंधान संस्थानों के पास वैज्ञानिक विशेषज्ञता है, स्टार्टअप उद्यमशीलता की ऊर्जा लेकर आते हैं, उद्योग जगत उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं और बाजार की जरूरतों को समझता है, जबकि निवेशक इस पूरी प्रक्रिया के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकते हैं।

जब ये सभी क्षमताएं एक साथ आती हैं, तो अनुसंधान को उपयोगी उत्पादों और सेवाओं में बदलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ईएसटीआईसी ऐसी साझेदारियों को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश का निर्णायक प्रश्न

आगामी विधानसभा चुनावों वाले राज्यों में सबसे अधिक चर्चा में है उत्तर प्रदेश, क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता इसी राज्य से होकर जाता है। ऐसे में, इस प्रदेश का विधानसभा चुनाव केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि कौन-सा दल किन जातियों का बड़ा गठजोड़ बना सकता है। असली प्रश्न यह है कि नागरिक अपनी सरकार से क्या अपेक्षा रखता है: सुरक्षा, अवसर, सम्मान और विकास या फिर शिकायत दर्ज कराने, नौकरी पाने और सरकारी लाभ तक पहुंचने के लिए किसी जातीय संरक्षक की तलाश? योगी आदित्यनाथ के पक्ष में मजबूत तर्क यही है कि उन्होंने राजनीति की दिशा को जातीय संरक्षण से निकालकर कानून के शासन की ओर मोड़ने का प्रयास किया है। अखिलेश यादव की राजनीति का केंद्रीय सूत्र 'पीडीए'-पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक-है। सामाजिक न्याय का प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रतिनिधित्व भी जरूरी है, मगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को केवल जातियों के जोड़-घटाव से नहीं चलाया जा सकता। राज्य तब आगे बढ़ता है जब हर नागरिक को यह भरोसा हो कि कानून उसकी जाति, पंथ, उपनाम देखकर नहीं बदलेगा। हाल की राजनीतिक भाषा में यह अंतर साफ दिखता है। 2017 से पहले प्रदेश में 'रूल आफ माफिया' था और अब 'रूल आफ ला' है। योगी का यह कथन केवल राजनीतिक नारा नहीं, शासन की स्पष्ट अवधारणा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपनी रणनीति को मुस्लिम-यादव आधार, पीडीए और युवाओं की नाराजगी के गठजोड़ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ओर राज्य की प्रकृति का प्रश्न है। दूसरी ओर सत्ता तक पहुंचने के लिए सामाजिक समूहों की चुनावी गोलबंदी। जाति का प्रश्न अप्रासंगिक नहीं है। उत्तर प्रदेश में वंचित रहे दलितों, पिछड़ों और कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व, आरक्षण, सम्मान और सुरक्षा चाहिए, लेकिन सामाजिक न्याय और जातिवादी राजनीतिक संरक्षण एक ही बात नहीं। किसी दलित-पिछड़े परिवार को अन्याय के समय यह आश्वासन नहीं चाहिए कि चुनाव बाद उसकी जाति की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ेगी। किसी गरीब पिछड़े युवा को सरकारी नौकरी के लिए निष्पक्ष परीक्षा चाहिए, किसी मंत्री या स्थानीय दलाल तक पहुंच नहीं। यदि थाने निष्पक्ष हों, भर्ती पारदर्शी हो, राशन और आवास योजना बिचौलियों के बिना मिले, सड़क और बिजली हर गांव तक पहुंचे, तो जाति की राजनीतिक निर्भरता स्वाभाविक रूप से कमजोर होगी। यह जाति की सामाजिक वास्तविकता से आंख चुराना नहीं। नागरिक को जाति-आधारित राजनीतिक संरक्षकत्व से मुक्त करना है। योगी शासन में 2017 से अब तक 9.5 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी गई हैं और आगे भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का लक्ष्य है। योगी सरकार का गैर-राजपत्रित समूह 'ख', 'ग' और 'घ' के अनेक पदों में साक्षात्कार की व्यवस्था समाप्त करने का फैसला भी महत्वपूर्ण रहा। साक्षात्कार वह स्तर था, जहां सिफारिश, पहचान और प्रभाव की आशंका सबसे अधिक होती थी। प्रतिनिधित्व के आंकड़े भी इस तर्क को बल देते हैं। 2024 में उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार लोक सेवा चयन आयोग की 46,675 नियुक्तियों में 17,929 चयनित अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से थे यानी लगभग 38.41 प्रतिशत। एससी-एसटी के चयनितों को जोड़ दें तो आरक्षित वर्गों की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक रही। यह आंकड़ा सभी सरकारी नियुक्तियों का समग्र चित्र नहीं है, फिर भी यह उस धारणा को चुनौती देता है कि वंचित समुदायों की प्रगति केवल उन्हीं दलों के माध्यम से संभव है, जो उनकी पहचान पर विशेष राजनीतिक दावा करते हैं। पीडीए के पक्ष में आवाज उठाते हुए सपा को यह भी स्पष्ट करना होगा कि राज्य की संस्थाओं को जातीय प्रभाव से मुक्त कैसे रखा जाएगा? छोटी और अति-पिछड़ी जातियां बड़े सामाजिक समूहों के वर्चस्व से कैसे बचेंगी? भर्ती में प्रभावशाली परिवारों और जातीय नेटवर्क की भूमिका कैसे खत्म होगी? कानून का राज तभी विश्वसनीय बनता है, जब सत्तारूढ़ दल से निकटता भी न्यायिक प्रक्रिया से बचाव की ढाल न बन सके। भाजपा विधायक रहे अशोक चंदेल को 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिली थी। कानून का राज विकास की पहली शर्त है। जिस प्रदेश में जमीन पर कब्जे का डर हो, माफिया का दबदबा हो, निवेशक असुरक्षित हो और गरीब को न्याय पाने के लिए सिफारिश खोजनी पड़े, वहां विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। कानून की समानता छोटे व्यापारी को भी उतना ही बल देती है, जितना बड़े उद्यमी को देती है। इसी तरह वह जितनी आजादी किसी आम परिवार की महिला देती है, उतनी ही संपन्न घर की नारी को। योगी सरकार का जाति-आधारित राजनीतिक रैलियों और पुलिस दस्तावेजों में अनावश्यक जाति-उल्लेख को सीमित करने का कदम इसी दिशा में देखा जाना चाहिए। इसका अर्थ जातिगत अत्याचार को नकारना नहीं हो सकता-एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून में जाति की पहचान आवश्यक है, पर सामान्य आपराधिक प्रक्रिया में नागरिक की पहचान जाति से पहले उसके अधिकारों और विधिक स्थिति से होनी चाहिए। योगी सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। पेपर लीक, पुलिस की मनमानी जैसी शिकायतों पर उसे संवेदनशील और कठोर, दोनों होना होगा। कानून का शासन केवल कठोर कार्रवाई का नाम नहीं। उसमें न्यायिक प्रक्रिया, संविधान की मर्यादा और निर्दोष के अधिकारों की सुरक्षा अनिवार्य है।

‘ऑब्सेशन’ के हिंदी वर्जन में वरुण धवन-कृति सेनन की एंट्री, ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने कमाए करोड़ों



हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर हॉरर फिल्म ‘ऑब्सेशन’ के ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन के बाद एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस कृति सनोन इसके हिंदी डब वर्जन में अपनी आवाज देंगे। हॉरर फिल्म ‘ऑब्सेशन’ ने दुनियाभर में 523 मिलियन डॉलर से ज्यादा कमाए। फिल्म का अनकट वर्जन 30 अक्टूबर 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। दर्शक फिल्म को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में देख सकेंगे। फिल्म की कहानी प्यार, जुनून और एक खतरनाक इच्छा के इर्द-गिर्द घूमती है। वरुण धवन और कृति सेनन की आवाज में मिलेगा डर का डोज हॉरर और थ्रिलर फिल्मों के शौकीनों के बीच अपनी एक खास जगह बनाने वाली अंतरराष्ट्रीय फिल्म ‘ऑब्सेशन’ ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। इस फिल्म की सक्सेस को देखते हुए मेकर्स ने इसके भारतीय फैंस के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा तैयार किया है। देश के दर्शकों को अपनी भाषा में इस खौफनाक अनुभव से रूबरू कराने के लिए बॉलीवुड के 2 फेमस स्टार्स इस प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं, जिससे लोगों की उत्सुकता कई गुना बढ़ गई है। ग्लोबली फिल्म ने तोड़े कमाई के नए रिकॉर्ड फिल्म ‘ऑब्सेशन’ के बॉक्स ऑफिस सफर पर नजर डालें तो इसने रिलीज के बाद से ही दुनिया भर के सिनेमाघरों में गर्दा उड़ा दिया है। बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार फिल्म ‘ऑब्सेशन’ ने शुरुआती समय में ही अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी और धीरे-धीरे इसके आंकड़े आसमान छूने लगे। अमेरिका समेत दुनिया भर के अलग-अलग बाजारों से बंपर कमाई करते हुए इस फिल्म का कुल ग्लोबल कलेक्शन 523.2 मिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है। इसके साथ ही भारत के बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने लगभग 84.90 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन और 100.96 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया है, जो इसकी जबरदस्त पॉपुलेरिटी को साफ बयां करता है। क्या है फिल्म की अनूठी कहानी हॉरर फिल्म ‘ऑब्सेशन’ की कहानी एक बेहद दिलचस्प और डरावने मोड़ पर आधारित है, जो दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखती है। कहानी बेयर नाम के एक म्यूजिक स्टोर कर्मचारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अपनी ही को-वर्कर निक्की से गहरा प्यार हो जाता है।

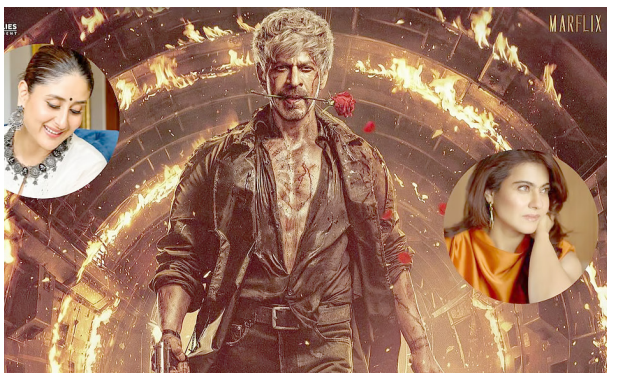
8 नंबर को अशुभ मानती हैं एकता कपूर? फैंस से पूछा नागिन के अगले सीजन का नाम



एकता कपूर ने नागिन के अगले सीजन के नाम को लेकर फैंस से सुझाव मांगे हैं। ज्योतिषीय कारणों से वह इसे नागिन 8 नहीं कहना चाहतीं। उन्होंने नागिन 7 2.0 और नागिन 9 जैसे विकल्प भी सुझाए। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी की जैसे आइकॉनिक सीरियल बनाने वाली एकता कपूर ज्योतिषीय में काफी विश्वास रखती है। बताया जाता है कि अपने सीरियल का नाम चुनने से पहले वे ज्योतिषी से सलाह जरूर लेती है। हाल ही में एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट नागिन के अगले सीजन को लेकर बड़ी बात कही है। नागिन 7 खत्म होने के बाद दर्शकों को बेसब्री से नागिन के अगले सीजन का इंतजार है। साथ ही ये भी उम्मीद की जा रही है कि इस सीरियल का नाम नागिन 8 हो सकता है। हालांकि एकता कपूर ने इस बात का खंडन किया है।

शाहरुख खान की फिल्म किंग का पोस्टर आते ही बॉलीवुड में हलचल, काजोल-करीना समेत कई स्टार्स ने लुटाया प्यार

सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ के नए पोस्टर पर करीना कपूर, काजोल और जोया अख्तर समेत कई दिग्गज स्टार्स ने अपना प्यार लुटाया है। शाहरुख खान की फिल्म किंग का पोस्टर पर बॉलीवुड स्टार्स का आया रिएक्शन। काजोल, करीना कपूर और जोया अख्तर समेत कई हस्तियों ने दिए रिएक्शन। महीप कपूर ने भी पोस्टर पर अपना रिएक्शन दिया। फिल्म को लेकर फैंस और बॉलीवुड स्टार्स के बीच उत्सुकता बनी हुई है। फिल्म इंडस्ट्री में इन दिनों बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की आने वाली फिल्म ‘किंग’ को लेकर चारों तरफ जबरदस्त क्रेज का माहौल बना हुआ है। हाल ही में जब शाहरुख खान ने अपनी इस मचअवेटेड फिल्म का नया पोस्टर दुनिया भर के सामने पेश किया, तो आम दर्शकों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारे भी खुद को रोक नहीं पाए। होठों के बीच गुलाब और आंखों में एक अलग ही तेवर लिए उनके इस नए और दमदार लुक ने सोशल मीडिया पर पहले ही सनसनी मचा रखी थी, और अब बॉलीवुड हस्तियों के रिएक्शन ने इस पर सोने पर सुहागा का काम किया है। स्टार्स के कमेंट सेक्शन में उमड़ा प्यार पोस्टर सामने आते ही इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बॉलीवुड स्टार्स ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी। एक्टर के इस बेखौफ और स्टाइलिश अंदाज को देखकर हर कोई उनकी तारीफ करने में जुट गया। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने दिल और आग वाले इमोजी के साथ इस पोस्टर पर अपना भरपूर प्यार बरसाया। वहीं दूसरी ओर एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी कई सारे फायर इमोजी शेयर करते हुए शाहरुख खान के इस नए और खतरनाक लुक के प्रति अपना जबरदस्त उत्साह जाहिर किया।



महीप कपूर और जोया अख्तर ने भी की तारीफ सिर्फ एक्ट्रेसेस ही नहीं बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के अन्य दिग्गज और क्रिएटिव चेहरे भी इस लिस्ट में पीछे नहीं रहे। फेमस फिल्ममेकर जोया अख्तर ने दिल, आग और आंखों में दिल वाले इमोजी के जरिए इस पोस्टर पर अपनी दीवानगी जाहिर की। इसके अलावा महीप कपूर और एक्ट्रेस सहर बंबा ने भी फायर और हार्ट इमोजी के साथ अपना रिएक्शन देते हुए इस लुक को शानदार बताया। इंडस्ट्री के इन तमाम बड़े नामों का इस तरह खुलकर अपने रिएक्शन देना यह साफ साबित करता है कि फिल्म के मेकर्स ने जो जादू पर्दे के पीछे बुना है, उसकी गूं इंडस्ट्री के अंदर भी साफ सुनाई दे रही है। साल के अंत में बॉक्स ऑफिस पर होगी महाएंट्री इस हाई-ऑक्टेन एक्शन एंटरटेनर का डायरेक्शन जाने-माने डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं, जिनकी फिल्मों का स्केल हमेशा से भव्य रहा है।

इसके निर्माण की जिम्मेदारी देश के प्रतिष्ठित बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स ने मिलकर उठाई है। निर्माताओं ने फिल्म किंग की रिलीज के लिए साल के आखिरी महीने को चुना है, और यह फिल्म आने वाले 24 दिसंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है।

अभिषेक की आंधी में उड़ी मेजबान टीम, भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया



न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी-20 मुकाबले में भारतीय टीम ने मेजबान टीम को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है। इस मैच में अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में भारत को 6 विकेट से जीत मिली। अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतकीय पारी खेली। 38 गेंदों में 113 रनों की पारी के साथ अभिषेक शर्मा ने मैच के नतीजे बदल दिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी-20 मुकाबले में भारतीय टीम ने मेजबान टीम को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी है।

पावरप्ले में सर्वाधिक रन, फिर तेज फिफ्टी; भारत के नाम दर्ज हुए ये 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे टी20 में 6 विकेट से हराकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पावरप्ले में 118 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। भारत ने तीसरे टी-20 मैच में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पावरप्ले में तोड़े 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत ने तीसरा टी-20 मैच जीतकर सीरीज पर जमाया कब्जा टीrम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। मंगलवार को वेलिंगटन में खेले गए तीसरे टी20 मैच में भारत ने मेजबान न्यूजीलैंड को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने पहले



बल्लेबाजी करते हुए 198/3 का मजबूत स्कोर खड़ा किया था, जिसे टीम इंडिया ने महज 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। भारत की इस धमाकेदार जीत के हीरो रहे सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, जिन्होंने कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं। भारतीय टीम की रिकॉर्ड साझेदारी दरअसल, लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को अभिषेक शर्मा और युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने आतिशी शुरुआत दिलाई। अभिषेक शर्मा ने महज 38 गेंदों में 113 रनों की तूफानी शतकीय पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 11 गगनचुंबी छक्के जड़े। उन्हें 10वें ओवर में काइल जैमीसन ने आउट किया। अभिषेक ने वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 133 रनों की विस्फोटक ओपनिंग पार्टनरशिप की। सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 45 रन बनाए, वे 8वें ओवर में मैथ्यू फिशर का शिकार बने। इनके अलावा संजू सैमसन ने 18 और कप्तान श्रेयस अय्यर ने 5 रनों का योगदान दिया। पावरप्ले के 6 ओवरों में भारत ने मचाई तबाही भारतीय बल्लेबाजों ने मैच के पावरप्ले में ही न्यूजीलैंड को मैच से पूरी तरह बाहर कर दिया था। भारत ने शुरुआती 6 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए रिकॉर्ड 118 रन कूट डाले।

ट्रंप-नेतन्याहू की दोस्ती से अमेरिकी राजनीति में दरार, इजरायल के खिलाफ क्यों बढ़ रही नाराजगी?

अमेरिका में इजरायल और प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर लोगों की राय तेजी से बदल रही है। प्यू रिसर्च के सर्वे में 60 प्रतिशत अमेरिकी इजरायल के प्रति नकारात्मक नजरिया रखते हैं। 60% अमेरिकी इजरायल के खिलाफ नकारात्मक राय रखते हैं। नेतन्याहू पर 59% अमेरिकियों को भरोसा नहीं है। डेमोक्रेट्स में इजरायल के प्रति नकारात्मक रुख बढ़ा। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राजनीति में विवाद का बड़ा मुद्दा बन गए हैं। उनकी नीतियों को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी में मतभेद गहरे हुए हैं, वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के बीच भी इजरायल को लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेता गाजा युद्ध में इजरायल की कार्रवाई और नेतन्याहू सरकार के रुख का विरोध कर रहे हैं। दूसरी ओर, ट्रंप के समर्थकों में एक धड़ा अमेरिका को विदेशी युद्धों से दूर रखने की वकालत कर रहा है, जबकि कुछ नेता नेतन्याहू के समर्थन में खड़े हैं। इजरायल को अमेरिकी मदद पर उठ रहे सवाल अमेरिका में लंबे समय से इजरायल के समर्थन में सक्रिय संगठन अमेरिकन इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमेटी (AIPAC) का दोनों प्रमुख पार्टियों में प्रभाव रहा है। हालांकि, इजरायल की सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिकी जनता



की बदलती राय के बीच डेमोक्रेटिक पार्टी में इस संगठन के प्रभाव पर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई में प्रतिनिधि सभा के कई डेमोक्रेट सांसदों ने इजरायल के लिए अरबों डॉलर की सहायता में कटौती के पक्ष में मतदान किया था। सितंबर में भी सीनेट के लगभग सभी डेमोक्रेट सांसदों ने वेस्ट बैंक में इजरायली हमलों से जुड़े मानवाधिकारों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए ट्रंप प्रशासन पर दबाव बनाने का समर्थन किया। ट्रंप और नेतन्याहू की नजदीकी पर भी चर्चा डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि नेतन्याहू के नेतृत्व में इजरायल को सैन्य सहायता जारी रखना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, कुछ सांसदों का कहना है कि इजरायल के साथ अमेरिका का रणनीतिक और सुरक्षा संबंध किसी एक प्रधानमंत्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी में भी इस मुद्दे पर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू का समर्थन किया है, जबकि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हें समर्थन देने से परहेज किया। रिपब्लिकन नेता माइक जॉनसन ने इसके विपरीत नेतन्याहू को अमेरिका का अच्छा साझेदार बताया है। सर्वे में इजरायल को लेकर बढ़ी नकारात्मक राय प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के अनुसार, 60 प्रतिशत अमेरिकी वयस्कों ने इजरायल के प्रति नकारात्मक राय जाहिर की। पिछले साल यह आंकड़ा 53 प्रतिशत था। वहीं, 59 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें विश्व मामलों में नेतन्याहू के सही फैसले लेने की क्षमता पर बहुत कम या बिल्कुल भरोसा नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों में यह बदलाव ज्यादा स्पष्ट है। सर्वे में 80 प्रतिशत डेमोक्रेट्स और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर झुकाव रखने वाले स्वतंत्र मतदाताओं ने इजरायल के प्रति नकारात्मक राय व्यक्त की। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इजरायल का मुद्दा अमेरिकी राजनीति में विदेश नीति से आगे बढ़कर दोनों पार्टियों के भीतर विचारधारात्मक बहस का हिस्सा बनता जा रहा है।

व्हाट्सप्प पर प्रचार किया और जीत गए राष्ट्रपति चुनाव! लूला ने खोला अपनी जीत का राज, बोले- पहला फोन खरीदना सफल



लूला डा सिल्वा ने ब्राजील चुनाव में जीत का श्रेय व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया को दिया। युवा वोटर्स, डिजिटल अभियान और कल्याणकारी योजनाओं ने भी अहम भूमिका निभाई। लूला डा सिल्वा ने दूसरे दौर में 51.8 प्रतिशत वैध वोट हासिल किए लूला ने अपनी चुनावी जीत में व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया की भूमिका बताई युवाओं के प्रदर्शन और डिजिटल अभियान से लूला के प्रचार को मजबूती मिली लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने लगातार दूसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर सबको चौंका दिया। इस जीत के साथ उनके चौथी बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया है। चुनाव के पहले दौर में दक्षिणपंथी फ्लेवियो बोल्सोनारो को बढ़त मिलने के बाद उन्हें अगला राष्ट्रपति बनने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। लूला ने पहले चरण में पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की और दूसरे और निर्णायक चरण में 51.8 प्रतिशत वैध वोट हासिल किया और लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति की कुर्सी पर कब्जा किया। लूला ने अपनी जीत को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अपनी चुनावी जीत के लिए सोशल नेटवर्किंग ऐप Whatsapp और सोशल मीडिया को श्रेय दिया। आइए आपको बताते हैं कि लूला की जीत में Whatsapp और सोशल मीडिया की क्या भूमिका था? युवा वोटर्स का समर्थन और सड़कों पर प्रदर्शन पहले दौर के नतीजों के बाद लूला के समर्थन में छात्र और युवा बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। रियो डी जनेरियो, साओ पाउलो और बेलो होरिजोंटे जैसे शहरों में लोगों ने उनके समर्थन में रैलियां निकालीं। इन प्रदर्शनों में सामाजिक कल्याण योजनाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। गेटुलियो वर्गास फाउंडेशन के राजनीतिक विशेषज्ञ एडुआर्डो ग्रिन के मुताबिक, युवाओं की एकजुटता ने लूला के अभियान को मजबूती दी।

हूतियों के सामने बेबस हुआ सऊदी अरब! हमले रोकने के लिए प्लेन में भरकर भिजवाया 1 अरब डॉलर, सीजफायर की अपील



इजरायली मीडिया का दावा है कि सऊदी अरब ने ईरान की मध्यस्थता से हूतियों को 1 अरब डॉलर देने का प्रस्ताव रखा है, ताकि वह तेल और ऊर्जा ठिकानों को निशाना न बनाएं। इजरायली मीडिया ने हूतियों को 1 अरब डॉलर देने के प्रस्ताव का दावा किया रिपोर्ट के मुताबिक, इस पहल में ईरान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है सऊदी अधिकारी ने कथित वित्तीय हस्तांतरण की पुष्टि नहीं की इजरायली मीडिया ने खाड़ी क्षेत्र के राजनयिक सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि सऊदी अरब ने ईरान की मध्यस्थता से यमन के हूती विद्रोही समूह को 1 अरब डॉलर देने का प्रस्ताव रखा है। कथित तौर पर इसका उद्देश्य सीजफायर सुनिश्चित करना और सऊदी अरब पर हूतियों के हमले रुकवाना है। हालांकि, इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान संभावित सीजफायर पर बातचीत के लिए तेहरान गए थे। इस कथित समझौते के तहत ईरान के माध्यम से हूती समूह को 1 अरब डॉलर हस्तांतरित किए जाने की बात कही गई है। 1 अरब डॉलर तेहरान ले गए थे सऊदी अधिकारी एक राजनयिक सूत्र ने दावा किया कि सऊदी रक्षा मंत्री हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान से तेहरान पहुंचे थे और अपने साथ रकम भी लेकर आए थे। हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सऊदी अधिकारी ने किसी भी तरह के वित्तीय हस्तांतरण की पुष्टि नहीं की। बैठक में कई देशों के प्रतिनिधि हुई शामिल इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बातचीत में तुर्की के खुफिया प्रमुख इब्राहिम कालिन और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के अलावा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव जनरल मोहसेन रेजाई और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

UAE में 12.90 करोड़ की लॉटरी जीतने वाला भारतीय कौन? वो गोल्डन वीजा क्यों चाहता है



UAE में भारतीय नागरिक ने 50 दिरहम की लॉटरी से करीब 12.9 करोड़ रुपये जीते। अब वह पत्नी के साथ दुनिया घूमने, परिवार संग समय बिताने और गोल्डन वीजा पाने का सपना पूरा करना चाहते हैं। UAE में भारतीय ने 50 दिरहम के टिकट से 50 लाख दिरहम जीते। 60वें जन्मदिन से पांच दिन पहले चमकी किस्मत, इनाम करीब 12.9 करोड़ रुपये। पत्नी के साथ दुनिया घूमने और UAE गोल्डन वीजा के लिए आवेदन करने की योजना। किस्मत कब और कैसे बदल जाए, कोई नहीं जानता। संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहने वाले एक भारतीय शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। किशोर पांडुरंग राव ने महज 50 दिरहम यानी करीब 1,300 रुपये की लॉटरी टिकट खरीदकर 5 मिलियन दिरहम (लगभग 12.9 करोड़ रुपये) का इनाम जीत लिया।

ब्राजील में लूला की जीत के बाद फ्लेवियो पर एक्शन, देश से बाहर जाने पर लगी रोक, पासपोर्ट जमा करने का आदेश

ब्राजील की कोर्ट ने विपक्षी नेता फ्लेवियो बोल्सोनारो के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है और 24 घंटे में पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। वकील से बात करने पर भी लगी रोक। ब्राजील की एक कोर्ट ने विपक्षी नेता फ्लेवियो बोल्सोनारो के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है। साथ ही 24 घंटे के अंदर अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश रविवार को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद आया। लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने फ्लेवियो को हराकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। ब्राजील की पब्लिक न्यूज एजेंसी एजेंसिया ब्रासिल ने बताया कि सर्वोच्च संघीय न्यायालय के जज एलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने यह गोपनीय फैसला सुनाया, जिसमें बोल्सोनारो को वकील विलर टोमाज से संपर्क करने पर भी रोक लगा दी गई है, जिनकी जांच



सीनेटर के साथ एक संदिग्ध मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में हो रही है। देश से भागने का कोई इरादा नहीं: फ्लेवियो बोल्सोनारो फ्लेवियो बोल्सोनारो ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए पासपोर्ट जमा करने के आदेश की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उन्हें यह नोटिस उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो से मिलने के बाद दिया गया था, जो ब्रासीलिया में अपने घर में नजरबंद हैं। उन्होंने कहा, मुझे सड़क पर ही अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया, और मुझे देश छोड़ने से भी मना किया गया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके भाई एडुआर्डो बोल्सोनारो की बातों पर आधारित था, जिन्होंने कथित तौर पर पिछले शुक्रवार को एक पॉडकास्ट में कहा था कि अगर फ्लेवियो चुनाव हार जाते हैं तो उन्हें ब्राजील छोड़ देना चाहिए। फ्लेवियो बोल्सोनारो ने कहा, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उनका देश से भागने का इरादा है। किस मामले में की गई कार्रवाई? इस फैसले से उनके सभी पासपोर्ट रद्द हो गए हैं, जिसमें सीनेटर के तौर पर उनके पास मौजूद राजनयिक पासपोर्ट भी शामिल है। यह फेडरल पुलिस की उस जांच का भी हिस्सा है जिसमें संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग और गैर-कानूनी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन शामिल है। जिसकी जांच चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्राजील के सर्वोच्च संघीय न्यायालय और फेडरल पुलिस ने मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

28 अक्टूबर जन्मदिवश पर विशेष।

स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं भगिनी निवेदिता, पूरा जीवन भारत को किया था समर्पित।

हसरत अली

इतिहास के पन्नों में ऐसे कई नाम छिपे हैं, जिनका भारत की उन्नति में योगदान अमूल्य है पर पीढ़ियां उन्हें भूलते जा रही है, उन्हीं कुछ नामों में से एक हैं स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत को समर्पित कर दिया। भारत के प्रति उनके प्रेम को उजागर करते हुए बिपिन चन्द्रपाल कहते हैं – "निवेदिता जिस प्रकार भारत को प्रेम करती हैं, भारतवासियों ने भी भारत को उतना प्रेम किया होगा – इसमें संदेह है"। 28 अक्टूबर, 1867 को जन्मीं निवेदिता का वास्तविक नाम 'मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल' था। एक अंग्रेजी- आइरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, शिक्षक एवं स्वामी विवेकानन्द की शिष्या- मार्गरेट ने 30 साल की उम्र में भारत को ही अपना घर बना लिया। मात्र 10 साल की उम्र में अपने पिता को खोने के बाद उनका जीवन



गरीबी में बीता। उनकी शिक्षा इंग्लैंड के एक चैरिटेबल बोर्डिंग स्कूल में हुई। सिर्फ 17 साल की उम्र में अपनी पढाई पूरी करने के बाद उन्होंने शिक्षक की नौकरी कर ली। 25 साल की उम्र में उन्होंने अपना भी एक स्कूल खोला और वह उस समय शिक्षा में अलग-अलग प्रयोग करने के लिए मशहूर थीं। इसके अलावा वे ज़िन्दगी का सच्चा सार जानना और समझना चाहती थीं और इसीलिए उन्हें महान विचारकों और सुधारकों की संगत बेहद पसंद थी। साल 1895 में मार्गरेट के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया। दरअसल, उन्हें एक निजी संगठन द्वारा एक 'हिन्दू योगी' का भाषण सुनने के लिए बुलाया गया था। यह योगी कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद थे। वह स्वामी जी के भाषण से इतना प्रभावित हुई की उन्होंने भारत आने का फैसला कर लिया। जब विवेकानंद मार्गरेट से मिले तो उन्हें भी समझ में आ गया कि मार्गरेट भारतीय महिलाओं के उत्थान में योगदान कर सकती हैं। मार्गरेट ने उसी पल यह मान लिया कि भारत ही उनकी कर्मभूमि है। इसके तीन साल बाद, जनवरी, 1898 में मार्गरेट भारत आ गयीं। स्वामी विवेकानंद ने उनको 25 मार्च 1898 को दीक्षा देकर भगवान बुद्ध के करुणा के पथ पर चलने की प्रेरणा दी। दीक्षा के समय स्वामी विवेकानंद ने उन्हें नया नाम 'निवेदिता' दिया, जिसका अर्थ है 'समर्पित' और बाद में वह पूरे देश में इसी नाम से विख्यात हुईं। दीक्षा प्राप्त करने के बाद निवेदिता कोलकाता के बागबाज़ार में बस गयीं। यहाँ पर उन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया। जहाँ पर वह लडकियों के माता-पिता को उन्हें पढ़ने भेजने के लिए प्रेरित करती थी। निवेदिता स्कूल का उद्घाटन रामकृष्ण परमहंस की पत्नी मां शारदा ने किया था। निवेदिता ने माँ शारदा के साथ बहुत समय बिताया। उस समय बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित थी और स्त्रियों के अधिकारों के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता था। पर निवेदिता को पता था कि केवल शिक्षा ही इन कुरूतियों से लड़ने में मददगार हो सकती है। उन्होंने अपने जीवन मे स्त्री शिक्षा के द्वारा भारत मे व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने का प्रयास किया।

हसरत अली

शेरपुर जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश

पृष्ठ 1/8 का शेष

यह न तो नेपाल है, न बांग्लादेश

निशाना साधते हुए शिंदे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे भारत को बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका बनाने की बात करते हैं। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि यह भारत है; यह न तो नेपाल है, न बांग्लादेश है और न ही श्रीलंका। लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए गहरी चिंता वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ता यह टकराव देश के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए गहरी चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक तरफ जहां गंभीर आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं दूसरी ओर तीखी बयानबाजी राजनीतिक सहिष्णुता के दायरे को लगातार सीमित कर रही है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की आलोचना या असहमति को राष्ट्रद्रोह या देशविरोधी बता देना स्वस्थ चर्चा की संस्कृति को कमजोर करता है। आवश्यक यह है कि राजनीतिक दल वैचारिक कटुता को छोड़कर संवैधानिक मर्यादाओं का सम्मान करें और देश के वास्तविक मुद्दों पर सार्थक विमर्श स्थापित करें।

मुंबई, ठाणे और भिवंडी के निवासियों

पूर्वी उपनगरों तथा बीएमसी द्वारा जल आपूर्ति प्राप्त करने वाले ठाणे और भिवंडी के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। बीएमसी ने इन सभी क्षेत्रों के निवासियों से आग्रह किया है कि वे अगले सात दिनों तक पीने के पानी को अच्छी तरह से उबालकर और छानकर ही उपयोग करें। प्रशासन द्वारा यह सुरक्षात्मक कदम जल आपूर्ति नेटवर्क में मरम्मत कार्य के बाद पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए उठाया गया है। येवाई मास्टर बैलेंसिंग रिजरवायर की मरम्मत पूरी बीएमसी से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिसे-पांजरापुर जल परिसर में स्थित येवाई मास्टर बैलेंसिंग रिजरवायर के कंपार्टमेंट 2 की मरम्मत का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। मरम्मत का कार्य संपन्न होने के पश्चात, इस कंपार्टमेंट 2 को बुधवार, 28 अक्टूबर को औपचारिक रूप से चालू किया जाएगा। बीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि जब मरम्मत किए गए कंपार्टमेंट को जल आपूर्ति प्रणाली में फिर से चालू किया जाता है, तो उस प्रक्रिया के दौरान पानी की गुणवत्ता पर अस्थायी असर पड़ सकता है। इसी वजह से मुंबई शहर के कुछ हिस्सों, पूर्वी उपनगरों और ठाणे व भिवंडी के उन क्षेत्रों में जहां बृहन्मुंबई मनपा पानी सप्लाई करती है, नागरिकों को अगले 7 दिनों के लिए पानी उबालने एवं छानने की सलाह दी गई है। जल संदूषण पर शिकायतें और भ्रांतियां हाल ही में मुंबई में पानी के दूषित होने की खबरों को लेकर सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स पर काफी चर्चाएं देखने को मिल रही थीं, जिससे आम लोगों में असमंजस और डर का माहौल बनने लगा था। इस संदर्भ में स्थिति को स्पष्ट करते हुए आंकड़े साझा किए गए, जिसके अनुसार बीएमसी को बीते आठ महीनों के दौरान दूषित पानी से संबंधित कुल 1,514 शिकायतें मिली हैं। हालांकि, यह विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि 1,514 शिकायतों का अर्थ यह कदापि नहीं है कि 1,514 जल के नमूने दूषित पाए गए हैं या फिर मुंबई की पूरी जलापूर्ति व्यवस्था असुरक्षित हो चुकी है। यद्यपि वितरण नेटवर्क में जल संदूषण होना एक गंभीर विषय है और प्रत्येक शिकायत की उचित जांच कर उसका निवारण किया जाना आवश्यक है, परंतु बिना किसी ठोस प्रमाण के पूरे शहर में दहशत फैलाना अनुचित है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इन्फ्लुएंसर्स को डर पैदा करने के बजाय जिम्मेदार तरीके से लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए। नागरिकों के लिए सतर्कता आवश्यक बुधवार, 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस 7 दिनों की अवधि के दौरान मुंबई शहर, ठाणे और भिवंडी के प्रभावित इलाकों के लोगों को बीएमसी के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। पीने का पानी उबालकर और छानकर प्रयोग करने से किसी भी संभावित स्वास्थ्य जोखिम से बचा जा सकता है।

महाराष्ट्र SIR मामले में सुप्रीम

अरविंद दातार ने कहा कि मुंबई और पुणे में पुनर्विकास के दौरान अस्थायी रूप से स्थानांतरित किए गए मतदाताओं के नाम 'व्यक्ति नहीं मिला' के रूप में हटा दिए गए हैं। महाराष्ट्र के कुल 9.79 करोड़ मतदाताओं में से लगभग दो करोड़ मतदाताओं के नाम मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और 1.22 करोड़ अन्य मतदाताओं के नाम तार्किक विसंगतियों के आधार पर हटा दिए गए हैं। जब तक शीर्ष अदालत इस मामले पर फैसला नहीं सुना देती, तब तक राज्य में एसआईआर को रोक दिया जाना चाहिए और किसी भी ऐसे मतदाता का नाम नहीं हटाया जाना चाहिए, जो एसआईआर से पहले की मतदाता सूची में शामिल था। शीर्ष अदालत ने इस मामले में अब केंद्र व चुनाव आयोग को नोटिस भेज कर पूछा है कि आखिर 1.22 करोड़ मतदाताओं के नाम किस आधार पर काटे गए हैं। अब इस मामले की सुनवाई के लिए 5 नवंबर की तारीख तय की गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा था कि पूरे महाराष्ट्र राज्य में 9,78,54,049 पंजीकृत मतदाताओं में से 2,06,88,487 मतदाताओं (यानी 21.14 प्रतिशत) को मतदाता सूची के मसौदे से हटा दिया गया है, - क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वे अपने पतों पर नहीं मिले। SIR आदेश में मतभेद नहीं सुको में चुनाव आयोग का हलफनामा, सर्वसम्मति से सभी फैसले इस बीच, चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि एसआईआर से जुड़े 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के आदेश सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने सीईसी ज्ञानेश कुमार पर एकतरफा फैसले लेने के आरोपों को खारिज किया। निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिकारियों और चुनाव आयुक्तों की टिप्पणियां, सवाल और सुझाव सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इन्हें आयोग का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। फॉर्म-6 नहीं बदला, खबर भी प्रमाणित नहीं आयोग ने सीईसी के कामकाज को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया। उसका कहना है कि याचिका मुख्य रूप से एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है और ऐसे आरोपों को स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया संविधान में तय है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया अपनानी होती है। एसआईआर के आदेशों से नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में कोई औपचारिक संशोधन नहीं किया गया। आयोग ने अदालत से आग्रह किया कि विस्तृत जवाब बाद में देने की सुविधा दी जाए।

95% मामलों में प्यार

झूठे वादे भी नाबालिगों को जोखिम में डाल सकते हैं। ऐसे मामलों में परिवारों और पुलिस की समय पर कार्रवाई महत्वपूर्ण होती है। सीसीटीवी की मदद से बच्ची की तलाश मुंबई शहर में गुमशुदा बच्चों की तलाश के दौरान सीसीटीवी फुटेज भी उपयोगी साबित होते हैं। खबर के अनुसार, 21 जुलाई को दादर की हिंदू कॉलोनी से लापता हुई सात वर्षीय बच्ची को माटुंगा पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से तलाश अभियान चलाकर ढूंढ निकाला। इसी दिन शिवड़ी की 13 वर्षीय छात्रा और अगस्त में भिवंडी से लापता हुईं दो 17 वर्षीय किशोरियों के मामलों में भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। नाबालिगों की गुमशुदगी के मामलों में त्वरित शिकायत, प्रभावी जांच और बच्चों की सुरक्षित वापसी सबसे महत्वपूर्ण है। आंकड़ों में बड़ी संख्या में मामले सुलझाए जाने के बावजूद हर मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए निरंतर निगरानी और सहायता जरूरी है।

महाराष्ट्र शालार्थ आईडी घोटाला

अनुसार, नाशिक विभाग में पहले चरण में 150 शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी मान्यता रद्द कर उनका वेतन रोक दिया गया है। इसके साथ ही विभाग में कुल 893 संदिग्ध मामलों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान नियुक्तियों से जुड़े दस्तावेजों, अनुमतियों और वेतन रिकॉर्ड का सत्यापन किया जा रहा है। इन मामलों की पड़ताल में अन्य अनियमितताएं सामने आने की भी आशंका है। जलगांव में 132 लोगों पर कार्रवाई जलगांव जिले में भी शालार्थ आईडी घोटाले से जुड़े मामलों में कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच के बाद 132 लोगों की मान्यता रद्द करने और वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य संदिग्ध नियुक्तियों और सरकारी वेतन से जुड़े कथित अनियमित मामलों की जांच करना है। नासिक पुलिस की एसआईटी कर रही जांच नासिक शहर के पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक के मार्गदर्शन में एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। टीम संदिग्ध नियुक्तियों से जुड़े दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच कर रही है। शुरुआत में शिक्षा विभाग से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की चर्चा थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अब प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। संदिग्ध नियुक्तियों के सत्यापन पर जोर शिक्षा विभाग अब नियुक्तियों की व्यक्तिगत मान्यता, वेतन भुगतान और संबंधित दस्तावेजों की वैधता की जांच कर रहा है। नासिक और जलगांव में हुई कार्रवाई के बाद अन्य संदिग्ध मामलों पर भी नजर रखी जा रही है। जांच पूरी होने के बाद ही घोटाले के वास्तविक दायरे और जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।

ज्ञानेश कुमार को हटाए बिना

और अब वे हमारे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ने वालों की आवाज दबाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।' हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक... उन्होंने आगे कहा, 'यह बात बिल्कुल साफ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मोदी-शाह के कठपुतली ज्ञानेश कुमार को हटा नहीं दिया जाता। अगर वे हमें यहीं रोकते हैं, तो हम अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के घर जाएंगे और वहां बड़ा धरना देंगे। हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं हो जाता।' दिल्ली पुलिस ने आरोपों का किया खंडन वहीं, कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रामलीला मैदान के लिए जारी एनओसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है और शर्तों के पालन के साथ रैली की अनुमति बरकरार है, जबकि होटल में कार्यक्रम की अनुमति का फैसला पूरी तरह प्रबंधन का निजी विषय है। समाचार एजेंसी एएनाई के अनुसार, होटल अशोका में होने वाली मॉक पार्लियामेंट के मामले में, दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह होटल पर निर्भर करता है, क्योंकि यह उनका निजी परिसर है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की थी कि कांग्रेस को 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रामलीला मैदान बुक करने के लिए 'नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) जारी किया गया था। पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि कांग्रेस ने दिल्ली नगर निगम (MCD) से जगह की उपलब्धता का प्रमाण पत्र लेने के बाद पुलिस से संपर्क किया था। दिल्ली पुलिस ने 1 नवंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली के लिए कुछ शर्तें तय की हैं- समय-सीमा का पालन- रैली को हर हाल में शाम 5 बजे तक समाप्त करना अनिवार्य होगा। भड़काऊ भाषणों पर पूर्ण रोक- मंच से ऐसा कोई भी भाषण या बयान नहीं दिया जाएगा, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द या कानून-व्यवस्था बिगड़े। CCTV निगरानी व कंट्रोल रूम- एंट्री-एग्जिट गेट, मंच, सिटिंग एरिया और आसपास के इलाकों में हाई-डेफिनिशन CCTV कैमरे लगाने होंगे, साथ ही 5 स्क्रीन वाला मॉनिटरिंग सिस्टम और कंट्रोल रूम स्थापित करना होगा। मूलभूत सुविधाओं का प्रबंध- रैली में शामिल होने वाले लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में पानी के टैंकर और महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट की पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। पहचान वाले वॉलंटियर्स की तैनाती- व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे स्वयंसेवकों को तैनात करना होगा जो एक जैसी ड्रेस (यूनिफॉर्म) या समान पहचान बैज पहने हों।

दिवाली से पहले फडणवीस कैबिनेट

जल संसाधन विभाग के 39,722 पदों के संशोधित ढांचे को हरी झंडी मिली है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 के अंत तक 58 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया है, जो 2016 के 45 लाख हेक्टेयर में 13 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त वृद्धि को दर्शाता है।

इस व्यवस्था के संचालन हेतु कुल 1,450 सिंचाई शाखा कार्यालयों (1,340 मौजूदा + 110 नए) के लिए पद सृजित किए जाएंगे और सिंचाई सहायक नामक नया संवर्ग गठित होगा।

इसके अलावा 5 महामंडलों के लिए 15 कार्यकारी अभियंता स्तर के विशेषज्ञ पदों का भी सृजन किया गया है।

पुणे के लोहगांव में भारत मंडपम की तर्ज पर राष्ट्रीय केंद्र पुणे को वैश्विक व्यापार और सम्मेलनों का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए लोहगांव में नई दिल्ली के 'भारत मंडपम' की तर्ज पर एक राष्ट्रीय स्तर का भव्य एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए पुणे मनपा की विकास योजना में लोहगांव स्थित खेल के मैदान के आरक्षण में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई है।

बजाज ऑटो को ई-व्हीकल निर्माण राज्य में पर्यावरण-अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन नीति के तहत बजाज ऑटो लिमिटेड को 66.82 करोड़ (66 करोड़ 82 लाख रुपये) की वित्तीय प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है।

शुगर कोटेड आईपीओ, निवेशकों के लिए कितनी टिकेगी शुगर कोटिंग?

बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील लिमिटेड के DRHP के मुताबिक, पिछले तीन वर्षों के दौरान PF, ESIC, TDS और GST जैसे टैक्स दायित्वों के भुगतानों में बार-बार देरी हुई है।

घरेलू उपकरण बनाने वाली कंपनियों की जरूरतों के मुताबिक स्टील कॉयल से उत्पाद तैयार कर उनकी आपूर्ति करने वाली महाराष्ट्र स्थित बॉम्बे कोटेड एंड स्पेशल स्टील लिमिटेड आईपीओ के जरिए पूंजी बाजार से करीब 183 करोड़ रुपये जुटाने जा रही है। कंपनी का आईपीओ 29 अक्टूबर से 2 नवंबर 2026 तक खुला रहेगा। इसके लिए 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर का प्राइस बैंड 76 से 82 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई में 5 नवंबर को होने की उम्मीद है। IPO का राशि कहां इस्तेमाल करेगी कंपनी? यह पूरी तरह फ्रेश इश्यू है। कंपनी की योजना इश्यू से मिलने वाली रकम में से 125 करोड़ रुपये पुराने कर्ज के भुगतान और करीब 15.7 करोड़ रुपये लीज व्यवस्था के तहत मशीनरी एवं उपकरण हासिल करने पर खर्च करने की है। शेष राशि का इस्तेमाल अन्य सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। स्टील कॉयल की बढ़ती लागत से मार्जिन पर दबाव की आशंका स्टील कॉयल कंपनी के कारोबार का प्रमुख कच्चा माल है।

भिवंडी मनपा क्षेत्र में जल्द दौड़ेंगी 100 इलेक्ट्रिक सिटी बसें

केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू होगी सेवा, चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम शुरू

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

भिवंडी शहर में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए महानगरपालिका जल्द ही 100 इलेक्ट्रिक सिटी बसें शुरू करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार के सहयोग से शुरू होने वाली इस योजना से शहरवासियों को सस्ते और सुविधाजनक सफर का विकल्प मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से शहर में सिटी बस सेवा शुरू करने की मांग की जा रही थी।

भिवंडी महानगरपालिका मुख्यालय में महापौर नारायण चौधरी की अध्यक्षता में हाल ही में बैठक हुई। इसमें भिवंडी और कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका के अधिकारियों के साथ प्रस्तावित बस सेवा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विधायक महेश चौघुले सहित मनपा के उपायुक्त और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

महापौर चौधरी के अनुसार, बस सेवा शुरू करने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में 4 चार्जिंग स्टेशन बनाने की तैयारी की जा रही है। कोंबड़पाड़ा, टेमघर, शांतिनगर और कल्याण रोड सहित अन्य क्षेत्रों में इसके लिए जगह



चिह्नित की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार, परिवहन विभाग और कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका के साथ समन्वय स्थापित कर योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।

नगरपालिका से महानगरपालिका बने भिवंडी को करीब 25 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अब तक शहर में मनपा की अपनी यात्री बस सेवा शुरू नहीं हो सकी है। प्रस्तावित योजना के तहत भिवंडी के साथ कल्याण और उल्हासनगर को जोड़ने वाली ई-बस सेवा शुरू करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके लिए तीनों शहरों के बीच समन्वय और परिवहन व्यवस्था की योजना बनाई जा रही है। सस्ते सफर के साथ प्रदूषण कम होने की उम्मीद

महापौर ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होने से नागरिकों को किफायती सार्वजनिक परिवहन मिलेगा। इससे निजी दोपहिया वाहनों पर निर्भरता कम करने और शहर में प्रदूषण घटाने में भी मदद मिल सकती है। बस सेवा से महानगरपालिका के लिए आय का एक नया स्रोत भी विकसित होने की उम्मीद है।

हालांकि, बसों के संचालन की शुरुआत, रूट, किराया और समय-सारणी को लेकर विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है। नागरिकों को अब इस योजना के धरातल पर उतरने और नियमित बस सेवा शुरू होने का इंतजार है।

महाराष्ट्र शालार्थ आईडी घोटाला: 150 शिक्षकों की मान्यता रद्द, वेतन पर रोक; 893 संदिग्ध मामलों की जांच जारी



महाराष्ट्र में फर्जी शालार्थ आईडी घोटाले पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। नासिक में 150 और जलगांव में 132 संदिग्ध शिक्षकों की मान्यता रद्द कर वेतन रोक दिया गया है। फर्जी शालार्थ आईडी मामले में शिक्षकों पर प्रशासनिक कार्रवाई तेज। नासिक में 150 शिक्षकों की मान्यता रद्द, वेतन रोका गया। नासिकमें 893 और जलगांव में 132 संदिग्ध मामलों पर कार्रवाई। महाराष्ट्र में कथित फर्जी शालार्थ आईडी घोटाले को लेकर शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक कार्रवाई तेज कर दी है। मामले में संदेह के घेरे में आए शिक्षकों की नियुक्तियों और वेतन संबंधी रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। विभाग ने संबंधित मामलों में वेतन रोकने और नियुक्तियों की व्यक्तिगत मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस कार्रवाई से सरकारी वेतन के कथित अनुचित लाभ से जुड़े मामलों की जांच में तेजी आने की उम्मीद है। नासिक में 150 शिक्षकों की मान्यता रद्द मिली जानकारी के ...शेष 7 पर

95% मामलों में प्यार बना वजह

मुंबई में नाबालिगों की गुमशुदगी पर पुलिस अलर्ट, 8 महीने में 875 मामले दर्ज

मुंबई में जनवरी से अगस्त 2026 के बीच नाबालिग लड़कियों के लापता होने के 875 मामले दर्ज हुए, जिनमें से पुलिस ने 97% (846) केस सफलतापूर्वक सुलझा लिए हैं। मुंबई में जनवरी-अगस्त 2026 के दौरान नाबालिग लड़कियों के 875 मामले दर्ज। पुलिस ने 846 मामले सुलझाए, अगस्त में 109 केस दर्ज हुए। हर पुलिस स्टेशन में गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए विशेष स्क्वॉड गठित। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी के मामले पुलिस प्रशासन के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। मुंबई पुलिस के जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी से अगस्त 2026 के बीच नाबालिग लड़कियों के लापता होने के 875 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 846 मामलों को सुलझाने का दावा किया गया है। यह कुल मामलों का लगभग 96.7 प्रतिशत है। वहीं, अगस्त महीने में गुमशुदगी के 109 मामले दर्ज हुए, जिनमें से 91 का



पता लगाया गया। हर पुलिस स्टेशन में विशेष मिसिंग स्क्वाड पुलिस के मुताबिक, नाबालिगों के लापता होने की सूचना मिलने पर तत्काल मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की जाती है। इसके लिए मुंबई के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में विशेष 'मिसिंग स्क्वाड' गठित किया गया है। इन टीमों का काम गुमशुदा बच्चों की तलाश करना, उपलब्ध सुरागों की जांच करना और उन्हें सुरक्षित बरामद करना है। कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लापता होने पर परिस्थितियों के अनुसार अपहरण से संबंधित मामला दर्ज किया जा सकता है। खबर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) का उल्लेख किया गया है। इस प्रावधान के सटीक कानूनी संदर्भ की प्रकाशन से पहले पुष्टि आवश्यक है। पारिवारिक विवाद और रिश्ते भी वजह पुलिस अधिकारियों के अनुसार, कई मामलों में लड़कियां अपनी मर्जी से या पारिवारिक विवादों के कारण घर छोड़ देती हैं। हालांकि, नाबालिग होने के कारण पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया अपनानी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में राज्य स्तर के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए बताया था कि 2021 से 2026 के बीच लापता महिलाओं के मामलों में लगभग 46.32 प्रतिशत मामले रोमांटिक रिश्तों और 20 प्रतिशत पारिवारिक समस्याओं से जुड़े थे। ये आंकड़े राज्य स्तर के बताए गए हैं, इसलिए इन्हें मुंबई के नाबालिगों के मामलों पर सीधे लागू नहीं किया जाना चाहिए। घरेलू हिंसा और सोशल मीडिया के जोखिम सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुछ परिवारों में मारपीट, भेदभाव और घरेलू हिंसा जैसी परिस्थितियां लड़कियों को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती हैं। वहीं, सोशल मीडिया या निजी संपर्कों के जरिए मिलने वाले ...शेष 7 पर

भिवंडी में मकान-दुकान किराए पर देने या बेचने पर पुलिस को देनी होगी जानकारी

7 दिन के भीतर किरायेदार और खरीदार का विवरण देना अनिवार्य, 14 दिसंबर 2026 तक आदेश लागू

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

भिवंडी शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में मकान, फ्लैट, दुकान, फार्म हाउस या अन्य संपत्ति किराए पर देने, सबलेट करने अथवा बेचने वाले मालिकों को अब संबंधित पुलिस थाने में इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा। ठाणे जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार, संपत्ति किराए पर देने या बेचने के बाद संबंधित किरायेदार अथवा खरीदार का विवरण सात दिनों के भीतर पुलिस को उपलब्ध कराना होगा। यह आदेश 14 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा। निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

ठाणे के जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल ने जिले में किरायेदारों और संपत्ति खरीदारों की जानकारी अद्यतन रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया है। प्रशासन के अनुसार, ठाणे ग्रामीण पुलिस क्षेत्र में भिवंडी-निजामपुर, कल्याण-डोंबिवली और उल्हासनगर जैसे शहरी क्षेत्र तथा कई औद्योगिक क्षेत्र, गोदाम और वेयरहाउस हैं। यहां रोजगार, कारोबार और अन्य कामों के लिए बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से लोग आते हैं और आसपास के इलाकों में किराए पर रहते हैं।

प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ संपत्ति मालिक किराएदारों की पहचान की उचित जांच किए बिना मकान, फ्लैट, दुकान, होटल या अन्य जगह किराए पर दे देते हैं। कई मामलों में पहचान संबंधी दस्तावेज भी नहीं लिए जाते और स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं दी जाती। ऐसे में संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने और कानून-व्यवस्था संबंधी संभावित समस्याओं को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।आदेश के तहत संबंधित संपत्ति मालिकों, किरायेदारों, सोसायटी के चेयरमैन और एस्टेट एजेंटों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुलिस को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी ऑनलाइन या निर्धारित सुविधाजनक माध्यम से संबंधित पुलिस थाने में दी जा सकती है।

ठाणे ग्रामीण पुलिस और संबंधित राजस्व क्षेत्र में आने वाले संपत्ति मालिकों को आदेश का पालन करने की अपील की गई है। मकान या दुकान किराए पर देने अथवा संपत्ति के हस्तांतरण के दौरान संबंधित व्यक्ति की पहचान और आवश्यक विवरण उपलब्ध कराना जरूरी होगा। प्रशासन का उद्देश्य जिले में रहने वाले लोगों की जानकारी का रिकॉर्ड व्यवस्थित रखना और संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण करना है।

भिवंडी में तेज आवाज में DJ बजाने पर मंडल आयोजक के खिलाफ केस दर्ज

बालाजीनगर टर्न पर नवरात्रि जुलूस के दौरान नियमों के उल्लंघन का आरोप

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान

भिवंडी के भंडारी कंपाउंड स्थित बालाजीनगर इलाके में नवरात्रि जुलूस के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में भोईवाड़ा पुलिस ने मंडल आयोजक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि जुलूस के दौरान निर्धारित नियमों की अनदेखी कर तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाया जा रहा था।

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 20 अक्टूबर 2026 को रात करीब 7:52 बजे पुलिस टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान भंडारी रोड स्थित बालाजीनगर टर्न पर श्री ओमकार मित्र मंडल की ओर से नवरात्रि उत्सव का जुलूस निकाला जा रहा था।

पुलिस के मुताबिक, जुलूस में उच्च क्षमता वाला डीजे साउंड सिस्टम तेज आवाज में बजाया जा रहा था।इस मामले में मंडल के आयोजक बताए गए स्वी व्यासमुनी गुप्ता, निवासी बालाजीनगर, भंडारी कंपाउंड, भिवंडी के खिलाफ सरकारी आदेशों की अवहेलना और सार्वजनिक उपद्रव से संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।

भोईवाड़ा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, 270 और 293 सहित महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

यह मामला 25 अक्टूबर 2026 को दर्ज किया गया।मामले की जांच पुलिस हवलदार शशिकांत खाडे कर रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, मामला दर्ज होने के समय आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी।

यह दैनिक मालक-मुद्रक-प्रकाशक, संपादक मोहम्मद शकील अब्दुल रफीक ने सिटी इन्टरप्राजेस धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे से प्रकाशित किया, मुख्य कार्या लय- धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे महाराष्ट्र।मुंबई कार्या लय- शॉप नं. 14 उपाध्याय इंडस्ट्रियल इस्टेट, दहिसर चेक नाका, मुंबई इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधीन होगा संपादक मो. शकील अ. रफीक : मो. 9869128483
Email : shakeelsahara@gmail.com / citynewsmumbai@gmail.com website : www.citynewsmumbai.in RNI No. : MAHHIN/2012/47486